क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्प्लेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक क्रांति समय

RNI.No.: GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्स्योरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्प्लेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्षः 1 अंकः 315, शनिवार, 15 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

सशक्ति योजना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल

नई दिल्ली एजेंसी। स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रन (एसपीयूडब्ल्यूएसी) द्वारा संचालित सशक्ति योजना को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वर्ष 2002 से शुरू हुई इस योजना के तहत दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट अब तक 9 लाख 80 हजार 456 महिलाओं, स्कूल व कॉलेज छात्राओं को प्रशिक्षित देकर सशक्त बना चुके हैं। एसपीयूडब्ल्यूएसी उपायुक्त गीता रानी वर्मा ने बताया कि 2017 के लिए यह अवार्ड दिल्ली पुलिस को दिया जा रहा है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के फरवरी 2019 संस्करण में यह प्रशस्ति पत्र छापा जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से 989 कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें 2 लाख 8 हजार 125 लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस वर्ष 30 नवम्बर तक ऐसे 320 कार्यक्रमों का आंकड़ा 54 हजार 954 है।

मायावती बोलीं, रक्षा संबंधित सौदों के लिए पारदर्शी नीति बनाए केंद्र

लखनऊ एजेंसी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संकट में घिरी केंद्र सरकार को थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेकर रक्षा व सैन्य जरूरतों से संबंधित खरीद के लिए दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति बनाए। मायावती ने कहा है कि रक्षा खरीदों के संबंध में देश की आमजनता की तमाम धारणाओं और आशंकाओं का उचित समाधान निकालना जरूरी है। इसके लिए सरकारी स्तर पर आधारभूत सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रक्षा संबंधी खरीद के मामले में केंद्र की सत्ता में ज्यादातर रही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इन मामलों में जनता की आशंका रही है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से कम नहीं हैं। कांग्रेस ने बोफोर्स का और भाजपा ने राफेल का आरोप झेला है। रक्षा सौदों के लिए दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति बनाकर आरोपों-प्रत्यारोपों के साथ ही इन मामलों में कोर्ट-कचहरी में जाने से बचा जा सकता है।

यूपी: महिला समेत चार लोगों पर तेजाब से हमला, हालत गंभीर

बरेली। यूपी के बरेली से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां के शाही गांव में एक महिला समेत चार लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया गया। सभी की हालत गंभीर है और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक जोड़ी चप्पल, एक पर्स और एक जग बरामद किया है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में महिला के पति मालिक प्रेमपाल के भाई समेत दो लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। महिला का पति गांव के ओमकार के पास नौकरी करता है।

यागराज में आगामी कुंभ मेले के लिए बृहस्पतिवार को ''नगर प्रवेश' शोभायात्रा में भाग लेते पंच दशम अटल अखाड़ा के साधु।

सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले गृह मंत्रालय को दिया आदेश

चाइल्ड पोर्नेग्राफी रोकने का दिशानिर्देश जल्द

नई दिल्ली एजेंसी। गृह मंत्रालय सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर ''चाइल्ड पोनरेग्राफी', बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित फोटो और वीडियो जैसी सामग्री पर रोक लगाने के लिए जल्द ही दिशा निर्देश और मानक प्रक्रिया बना रही है।

इसे दो सप्ताह में लागू कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने एक गैरसरकारी संगठन की याचिका पर दो दिन पहले ही गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया था।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मंत्रालय जल्द ही यह दिशा निर्देश और मानक प्रक्रिया तैयार कर इन्हें लागू करेगा।

इस वेबसाइट पर की गई शिकायतों के माध्यम से अब तक 26 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वेबसाइट को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर बाल पोनरेग्राफी तथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कुछ महीने पहले ही साइबरक्राइम डाट गोव डाट इन वेबसाइट लांच की थी।

इस वेबसाइट पर की गई शिकायतों के माध्यम से अब तक 26 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वेबसाइट को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।

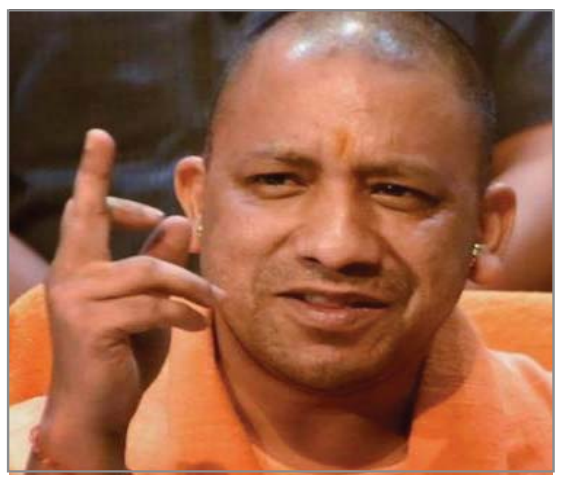

राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी का बयान, कांग्रेस का झूठ हुआ उजागर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस का झूठ और फरेब उजागर हो गया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर षड्यंत्र कर दुस्साहसिक कार्य किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने गहराई में जाकर इस मामले को देखा है। कांग्रेस देश के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह भी कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा की आवश्यकता को लंबित करने की दोषी है। राहुल गांधी की टिप्पणियां और झूठे आरोप लगाए , देश की जनता और सेना से माफी मांगे राहुल गांधी। देश के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों से ध्यान डाइवर्ट कराने का दुष्चक्र था। देश की जनता और सेना से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।

राहुल को बताना चाहिए कि किसके कहने पर, ऐसा किया। कांग्रेस का झूठ आज बेनकाब हुआ है। राहुल को अपने सोर्स का खुलासा करना चाहिए। राहुल ने देश की सुरक्षा की अनदेखी की है। योगी ने कहा, इस देश मे लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य कांग्रेस ने किया है। योगी ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने राफेल मुद्दे को तूल दिया और केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की।

एम थ्री ईवीएम मशीन से होंगे लोकसभा चुनाव

आभा स्वामी सीतापुर। आगामी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग अत्याधुनिक एम थ्री ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करेगा। इसमें गड़बड़ी की आशंका न के बराबर है। गड़बडी होने पर मशीन फैक्ट्री मॉड में चली जाएगी। मशीन में कोई कमी होगी तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेंगी। इन दिनों एम थ्री ईवीएम मशीनों की जांच सीतापुर में चल रही है।

पिछले चुनावों में कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की शुचिता पर प्रश्न खड़े किए थे। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने वोटिंग और काउंटिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नई ईवीएम मशीनों को लाने का निर्णय किया। किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने की क्षमता रखने वाली ईवीएम मशीनों के निर्माण का जिम्मा रक्षा मंत्रालय की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय की कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया को दिया गया। दोनों कम्पनियों ने मिलकर नई ईवीएम मशीन का एम थ्री वर्जन डेवलप किया है। इन दिनों सीतापुर में चल रही जांच प्रक्रिया के नोडल अधिकारी संतोष कुमार कहते हैं कि एम थ्री ईवीएम मशीन पहले की मशीन से ज्यादा कार्यकुशल और पारदर्शितापूर्ण है। बूथ कैप्चरिंग व किसी तरह की गड़बड़ी होने पर मशीन स्वतः फैक्ट्री मोड में चली जाएगी, यानी काम करना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारों को इसे बदलना होगा।

स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी गड़बड़ी:

अत्याधुनिक एम थ्री ईवीएम मशीन स्टार्ट होते ही स्वतः सब कुछ चेक करेगी। कोई गड़बड़ी होगी तो वह स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगी। इससे कर्मचारियों को कमी का पता लग जाएगा और आसानी ठीक की जा सकेगी। नोडल अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि मशीन बीवी पैड को भी सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इसमें काउंटिंग भी पुरानी मशीनों से तेज होगी।

एक मशीन से चल जाएंगे 24 बैलेट यूनिट:

एम थ्री ईवीएम मशीन पहले की मशीनों से ज्यादा कार्यकुशल है। नोडल अधिकारी ने बताया कि पहले की मशीनों में सिर्फ चार बैलेट यूनिट यानी 64 बैलेट ऑपरेट हो पाते थे। उन्होंने कहा कि एम थ्री मशीन से 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती हैं यानी 384 बैलेट ऑपरेट हो जाएंगे। एक बैलेट यूनिट में 16 बैलेट होते हैं।

चलन से बाहर हुई साढ़े नौ लाख पुरानी मशीनें:

निर्वाचन आयोग अबतक 9,30,430 एम टू ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल चुनाव में कर रहा था। इसे आयोग ने वर्ष 2006 में खरीदा था। एम थ्री मशीनों के आने से एम टू ईवीएम मशीनें चलन से बाहर हो जाएंगी।

यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी घोटाला मामले में तीसरा आरोपी सत्येंद्र चौहान गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा एजेंसी। यमुना प्राधिकरण में हुए भ्रष्टाचार का तीसरा अभियुक्त सत्येंद्र पुलिस हिरासत में ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण में हुए 126 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में पुलिस ने शुक्रवार को तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पूर्व आईएएस पीसी गुप्ता सहित दो लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीओ (ग्रेटर नोएडा) निशांक शर्मा ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए 126 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिल में दाता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सत्येंद्र चौहान को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। यमुना प्राधिकरण में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में थाना कासना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त सत्येंद्र S/O खेमचंद को क्द्य- कासना #NoidaPolice ने किया गिरफ्तार यमुना प्राधिकरण में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में थाना कासना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त सत्येंद्र s/o खेमचंद की गिरफ्तारी के संबंध म उन्होंने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को दाता इंफ्रास्ट्रक्चर के ही एक अन्य निदेशक रमेश बंसल को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व यमुना विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीसी गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जेल में हैं। मामले की जांच अभी जारी है। इसमें कुछ और लोगों के संलिप्त होने की आशंका है। जल्दी ही उनके नाम पता कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।

यूपी : हाईटेंशन लाइन गिरने से जिंदा जला किसान

बहराइच। लखनऊ -बहराइच हाईवे पर देवलखा चौराहे से लगभग पांच सौ मीटर आगे पटरी पर खड़ी गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्राली बिजली के पोल से जा टकराई। जिससे हाईटेंशन तार टूटकर ट्रैक्टर पर आ गिरा। इस हादसे में किसान की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली व गन्ने की फसल भी आग की लपटों में घिर कर नष्ट हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कैसरगंज थाने के गोड़हिया नम्बर दो के मजरे ठेकेदारपुरवा गांव निवासी रामसंवारे (35) पुत्र मैकूलाल शुक्रवार की भोर लगभग चार बजे अपना गन्ना ट्रैक्टर ट्राली पर लादकर पारले चीनी मिल ले जा रहे थे। देवलखा चौराहे से आगे लगभग पांच सौ मीटर दूरी पर लखनऊ - बहराइच हाईवे पर सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्राली खडी करके किसान का भतीजा उर्मिल लघुशंका करने लगा। इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से ठोकर मार दी। जिससे ट्राली हाईवे किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर के बाद हाईटेंशन तार टूटकर सीधे किसान के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में किसान जिंदा जल गया। हादसा होते ही मोरंग लदा ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। जानकारी होते ही एसएचओ संतोष कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अशोक कुमार जायसवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एसएचओ ने बताया कि मृतक के भाई फूलचंद्र की तहरीर पर फरार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। ट्रक पुलिस के कब्जे में है।

»»» हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा बाबा का अब तक क्यों नहीं पता चला

बाबा वीरेन्द्र देव को अब तक न खोज पाने पर सीबीआई को लताड़

अगली सुनवाई के दिन आश्रम की जांच करने वाले डीसीपी व महिला आयोग अध्यक्ष को भी पेश होने को कहा

नई दिल्ली एजेंसी। रोहिणी के विजय विहार में आश्रम स्थापित करनेवाले फरार बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित का अभी तक पता न लगने पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि बाबा का अभी तक क्यों नहीं पता चला। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने कहा कि सीबीआई मांफी मांगनेवाले लड़कियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन बाबा के बारे में कुछ नहीं बता रही। पीठ ने इस पर अगली सुनवाई के दिन सीबीआई के संबंधित अधिकारी को पेश होने को कहा है। उसने आश्रम की जांच करनेवाले संबंधित डीसीपी व महिला आयोग के अध्यक्ष से भी अगले सुनवाई के दिन पेश होने को कहते हुये सुनवाई 4 फरवरी के लिये स्थगित कर दी है।

कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह बलात्कार को लेकर की गयी जांच के बारे में बताये और उसको लेकर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। उसने 11 सितम्बर व 30 अक्टूबर की रिपोर्ट को भी अपने पास रख लिया और सभी से अगली रिपोर्ट पेश करने को कहा। उसने तत्कालिन रोहणी के डीसीपी से पूछा है कि जिन लड़कियों ने पुलिस व वकीलों को बंधक बनाने को लेकर माफी मांग ली है उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई बंद कर दी जाये। पुलिस इस मामले में आरोपी लड़कियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

मामले के अनुसार कोर्ट ने राम रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुये विजय विहार स्थित आध्यात्मिक आश्रम का निरीक्षण करने का निर्देश दो वकीलों, महिला आयोग व दिल्ली पुलिस को 19 दिसंबर को दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केवी मुत्तुकुमार ने कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता के बेटी को आश्रम में बंधक बना कर रख लिया गया है और उससे उसके बेटी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी करे।

कोर्ट ने इसपर वकील व महिला आयोग को जांच करने को कहा था। टीम ने विजय विहार व अन्य स्थानों से आध्यात्मिक शिक्षा देने के नाम पर बंधक बनाये गये 48 लड़कियों को पुलिस की मदद से छुड़ाया था। आश्रम में निरीक्षण करने गये टीम के सदस्यों को कई घंटे तक प्रवेश नहीं करने दिया गया था और उसके साथ मारपीट कर बंधक बना लिया गया था।

नई दिल्ली स्थित चिड़ियाघर में बृहस्पतिवार को चिम्पैंजी रीता के 59वें जन्मदिन पर बच्चों के साथ केक काटतीं दिल्ली चिड़ियाघर की डायरेक्टर रेनू सिंह।

संपादकीय

हंगामे की भेंट चढ़ना

संसद की कार्यवाही का लगातार हंगामे की भेंट चढ़ना दुखद है। चुनाव में जीत-हार संसदीय लोकतंत्र की स्वाभाविक स्थिति है। भविष्य के चुनावों के लिए पार्टियां और नेता अपनी राजनीतिक रणनीति के अनुरूप काम करें यह भी अस्वाभाविक नहीं है। किंतु संसद को राजनीतिक रणनीतियों की भेंट चढ़ा दिया जाए यह अस्वीकार्य है। कांग्रेस राफेल मुद्दे को जिस तरह उठा रही है, वह उसकी राजनीतिक रणनीति है। वह लोक सभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। तीन राज्यों की विधानसभा चुनावों में मिली जीत ने उसका उत्साह भी बढ़ाया होगा। किंतु वह यह समझने की भूल न करे कि संसद में हंगामा करने के कारण उसको विजय मिली है। कोई स्वस्थ मस्तिष्क का मतदाता संसद में हंगामे को अच्छी नजर से नहीं देखता। राफेल को कांग्रेस अगले आम चुनाव के पूर्व बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि राफेल सौदे का सच वह नहीं है जो कांग्रेस बात रही है। बावजूद इसके विपक्ष के रूप में चुनावी लाभ के लिए वह इसे भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है तो करे। उसका जो मत है, उसे प्रकट करे। किंतु इसके लिए जनता के बीच जाए। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी को यह अच्छी तरह मालूम है कि संसद की कार्यवाही के कुछ नियम हैं और उसके तहत ही उसे चलाया जा सकता है। लोक सभा में उसे लाना चाहती है तो नियमों की तरह लाए। कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देना मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका थी, लेकिन इसके बाद उसे सभापति पर छोड़ देना चाहिए। इसके लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना को इसी समय राममंदिर का निर्माण चाहिए। दोनों पार्टियों के हंगामे के कारण लोक सभा चल नहीं पा रही है। राज्य सभा भी हंगामे की भेंट चढ़ी है। हालांकि सरकार ने वहां हंगामे के बीच विधेयक पारित कराए। कांग्रेस समझती है कि संसद में हंगामा कर वह संदेश दे सकती है कि भाजपा इस मसले से भाग रही है तो शिवेसना महाराष्ट्र में हिन्दुत्व का ध्वजवाहक साबित कर अपने जनाधार की वापसी और भाजपा को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। क्या देश यह नहीं समझ रहा कि मंदिर मामले पर शिवसेना मोदी सरकार की निंदा के अलावा कोई प्रयास नहीं कर रही? हमारा मानना है कि पार्टियां राजनीति के साथ अपना संसदीय दायित्व भी समझें। कांग्रेस के लिए यह संदेश देना ज्यादा लाभदायी हो सकता है कि सरकार को घेरते हुए भी वह संसद में उत्तरदायी पार्टी की भूमिका निभा रही है।

सरकार और रिजर्व बैंक के बीच सेतु

शिकांत दास को ऐसे समय भारतीय रिजर्व बैंक की कमान मिली है जब उसकी स्वायत्तता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। इसमें उनका यह बयान आास्त करता है कि वे स्वायत्तता को बनाए रखेंगे। उर्जित पटेल के इस्तीफे के एक दिन के अंदर ही उनकी नियुक्ति का अर्थ है कि सरकार रिजर्व बैंक को लेकर गंभीर है। दास आर्थिक मामलों के सचिव तथा वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। जाहिर है, सरकार की आर्थिक व वित्तीय नीतियों का उन्हें पूरा अनुभव है। यूपीए सरकार में भी उनकी भूमिका काफी प्रमुख थी। नोटबंदी के समय सरकार और रिजर्व बैंक के बीच सेतु की भूमिका निभाकर उन्होंने स्थिति को तो संभाला ही था, जीएसटी पर राज्यों के बीच सहमति बनाने में भी उनकी मुख्य भूमिका थी। इसके लिए जीएसटी में जितने संशोधन हुए वे सबसे जुड़े थे। इनसे यह उम्मीद बंधती है कि नई जिम्मेवारी का भी वे सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे। जो कुछ सामने आया है, उससे साफहै कि सरकार इस समय केन्द्रीय बैंक के सुरक्षित कोष की समीक्षा इस लक्ष्य से करना चाहती है कि कितना उसमें रहना चाहिए एवं कितने का समुचित उपयोग किया जा सकता है। सरकार लघु और मध्यम उद्योगों को कर्ज देने में उदारता चाहती है। यह तभी संभव होगा जब बैंकों के पास पर्याप्त राशि रहे। देश में विकास संतुलन एवं रोजगार सृजन के लिए यह आवश्यक है। इसीलिए वह कुछ सरकारी बैंकों को प्रोफिट करेक्टिव ऐक्शन की परिधि से भी बाहर निकालना चाहती है। सरकार रिजर्व बैंक के अभी तक के प्रशासनिक ढांचे तथा कार्यपणाली में भी बदलाव चाहती है ताकि भविष्य में मतभेद की गुंजाइश कम रहे एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में बैंकिंग तंत्र बाधा न बने। इन सबके लिए रिजर्व बैंक के साथ संतुलित संबंध होना चाहिए। उर्जित के समय यह नहीं हो सका तो इसका अर्थ यही है कि ऊपरी तौर पर संतुलन बिठाना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। आखिर उर्जित भी सरकार की पसंद थे। इसी से गवर्नर के रूप में दास की चुनौतियों का आभास हो जाता है। किंतु रास्ता निकालना कठिन भी नहीं है। देश की जरूरतों के अनुरूप यदि केंद्रीय बैंक के व्यवहार में परिवर्तन चाहिए तो वैसा करने में तब तक कोई समस्या नहीं है, जब तक कि निर्णय करने की उसकी स्वायत्तता तथा वित्त को संभालने की जिम्मेवारी पर जोखिम न आए। यही महत्त्वपूर्ण है। देश चाहेगा कि दास इन कसौटियों पर खरे उतरें और विवाद समाप्त हो।

चुनाव नतीजों का राष्ट्रीय महत्त्व

लोक सभा के चुनाव के बाद से महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और असम आदि राज्यों की जीत का श्रेय उन्हीं को दिया जाता रहा था। लेकिन अब वे अपनी पार्टी के परंपरागत गढ़ों में ही फेल हो गए हैं।इन तीनों राज्यों में भाजपा की यह हार, लोक सभा और विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों में उसकी एक-के-बाद एक कई हार के बाद आई है। 2018 के जनवरी से, देश भर में 13 लोक सभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 3 में ही भाजपा और उसके सहयोगियों को जीत मिली थी, जबकि भाजपा से उसकी 5 सीटें, विपक्ष ने छीन ली थीं। इसी प्रकार, 22 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिनमें से सिर्फ5 पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी।

सतीश पेडणोकर

विधानसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें थीं और इनमें से दो राज्यों-मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़-में भाजपा पंद्रह साल यानी लगातार तीन कार्यकाल से राज कर रही थी। इन तीनों भाजपा शासित राज्यों के चुनाव नतीजों का राष्ट्रीय महत्त्व है। 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए सबसे बड़ा धक्का यही है। क्योंकि इन तीनों राज्यों को इस पार्टी का गढ़ माना जाता है। इन राज्यों की हार ने अजेयता की उस छवि को भी ध्वस्त कर दिया है, जो मोदी-शाह की जोड़ी के गिर्द भाजपा ने बड़ी कसरत से गढ़ी थी।

2014 के लोक सभा के चुनाव के बाद से महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और असम आदि राज्यों की जीत का श्रेय उन्हीं को दिया जाता रहा था। लेकिन अब वे अपनी पार्टी के परंपरागत गढ़ों में ही फेल हो गए हैं।इन तीनों राज्यों में भाजपा की यह हार, लोक सभा और विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों में उसकी एक-के-बाद एक कई हार के बाद आई है। 2018 के जनवरी से, देश भर में 13 लोक सभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 3 में ही भाजपा और उसके सहयोगियों को जीत मिली थी, जबकि भाजपा से उसकी 5 सीटें, विपक्ष ने छीन ली थीं। इसी प्रकार, 22 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिनमें से सिर्फ5 पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी।

बड़े पैमाने पर किसानों की बदहाली, नोटबंदी के प्रतिकूल परिणामों, रोजगार मुहैया कराने में विफलता, भ्रष्टाचार और कुशासन की मार भाजपा पर पड़ी है। इस जन-असंतोष को भांपकर, भाजपा-आरएसएस जोड़ी ने फिर से अपने सांप्रदायिक हिन्दुत्ववादी एजेंडा को आगे कर दिया है, ताकि ध्रुवीकरण कर सके और उसके जरिए समर्थन जुटा सके। इन तीनों राज्यों में चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जमकर उपयोग किया गया था और उन्होंने खुल्लम-खुल्ला सांप्रदायिक और मुस्लिम-द्वेषी बोली का प्रयोग किया था। इस चुनाव में उन्होंने 73 रैलियों को संबोधित किया था। इसके बाद भी भाजपा सरकारों से प्रबल नाराजगी और जनअसंतोष पर काबू नहीं पा सकी।

इन तीन राज्यों के चुनाव परिणामों का, आने वाले लोक सभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। आम तौर पर यही रुझान देखने में आया है कि जो पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, छह महीने के अंदर हों तो इन राज्यों में लोक सभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने इन राज्यों की कुल 65 सीटों में से 62 जीती थीं। इस विधासभा चुनाव का रुझान अगर कायम रहता है, तो भाजपा इन तीनों राज्यों में बड़ी संख्या में सीटें हारने जा रही है। इन तीनों राज्यों में चुनावी मुकाबला हमेशा से द्विधुवीय यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है। इस तरह, जब भी जनता भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है, कांग्रेस की जीत खुद-ब-खुद हो जाती है। इसके बावजूद, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो, राजस्थान में कांग्रेस मुश्किल से बहुमत हासिल कर पाई है और मध्य प्रदेश में बहुमत से सिर्फ दो सीट पीछे रह गई है। जनअसंतोष और सरकार से नाराजगी जितनी ज्यादा थी, उसे देखते हुए कांग्रेस को इन दोनों राज्यों में भी और निर्णायक जीत हासिल करने में समर्थ होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसकी छानबीन की जरूरत है। एक पहलू तो यही है कि इन दोनों राज्यों में कांगेस ने, हिन्दुत्ववादी मंच से कुछ मुद्दे उधार लेने की कोशिश की थी, मगर ऐसी मांगें उठाने का उन्हें कोई चुनावी लाभ नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि हिन्दुत्व के मंच से आकर्षित होने वाले लोग हमेशा, मूल हिन्दुत्ववादी पार्टी को ही पसंद करते हैं, न कि उसकी नकल करने वाली पार्टी को। जनता ने कांग्रेस के लिए इसलिए वोट डाले हैं कि वह किसानों की समस्याओं को हल करने, रोजगार पैदा करने और आजीविकाओं की रक्षा करने में, भाजपा की सरकारों की विफलता के लिए, उन्हें सजा देना चाहती है। जनता ने इस तरह भाजपा की राज्य सरकारों के कुशासन के रिकार्ड के खिलाफही अपना फैसला नहीं सुनाया है। जनता के गुस्से का एक बड़ा कारण तो नोटबंदी और जीएसटी के लागू किए जाने के जरिए थोपे गए बोझ ही थे। काफी संख्या में शहरी सीटों पर भाजपा की हार, इसकी गवाही देती है। पुन: केंद्र सरकार के इशारे पर ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें मजदूर विरोधी कानून लाई थीं और उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को कमजोर किया था।

राजस्थान सरकार तो, सार्वजनिक वितरण पणाली और प्राथमिक स्वास्स सेवा के निजीकरण की भी अगुवा थी। हालांकि, 2013 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा के मत फीसद में कमी हुई है, फिर भी इस चुनाव में उसे काफी वोट मिला है। मध्य प्रदेश में उसे 41 फीसद वोट मिले हैं और राजस्थान में 38.8 फीसद। वास्तव में मध्य प्रदेश में तो भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले, 0.1 फीसद वोट ज्यादा ही मिला है, जबकि राजस्थान में उसका मत फीसद, कांग्रेस के मुकाबले सिर्फ 0.5 फीसद ज्यादा रहा है। यह इसी की संभावना को दिखाता है कि अपने पक्ष में जरा सा झुकाव आने से ही भाजपा, फिर आगे निकल सकती है। यह इसकी संभावना की ओर भी इशारा करता है कि भाजपा-आरएसएस जोड़ी, लोक सभा चुनाव के लिए अपने सांप्रदायिक एजेंडा की आंच और तेज कर सकती है। इसलिए इन राज्यों में बनने वाली नई सरकारों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि किसानी के संकट, रोजगार निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के मुद्दों को फौरन हाथ में लें। वे सांप्रदायिक गतिविधियों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपना सकती हैं और उन्हें गुंडागर्दी और भीड़ हत्याओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। देश के पैमाने पर अपने प्रभाव को दोबारा हासिल करने के लिए, कांग्रेस को अब भी काफी मशक्कत करनी होगी। तेलंगाना में उसको लगा धक्का और उसका मिजोरम की पूर्वोत्तर की अपनी इकलौती सरकार को खो देना, इसी को दिखाता है।

सीपीआइ (एम) और वामपंथ के लिए, राजस्थान में दो सीटों पर जीत, इकलौता सकारात्मक नतीजा है। यह मुसलसल किसान संघर्षो का ही नतीजा है। कुल मिलाकर, इन विधानसभा चुनावों में भाजपा को और मोदी-शाह के नेतृत्व को धक्का लगा है। यह लोक सभा चुनाव भाजपा को शिकस्त देने की आने वाली लड़ाई के लिए, गति मुहैया कराएगी, जिसकी बहुत जरूरत थी।

चलते चलते

लापरवाह चालक

देश में जितनी मौतें बीमारियों या आतंकवादी घटनाओं में नहीं होती हैं, उनसे कहीं ज्यादा सड़क हादसों में होती है। सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में की गई यह सख्त टिप्पणी बताती है कि भारत में सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का आलम क्या रहता है? हालांकि सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी सड़कों की बेहद जर्जर और खराब हालत की वजह से आई है। खराब सड़क लोगों की मौत की अहम वजह तो हैं मगर लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते भी कई लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। कुछ लोग शराब पीकर किसी को कुचल देते हैं तो कोई नींद में गाड़ी चलाने के कारण सड़क पर खून बहा देते हैं। हालिया खबरों पर नजर दौड़ाएं तो लापरवाही से गाड़ी चलाने और इस वजह से कुछ लोगों की मौत की खबरें मीडिया

सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में की गई यह सख्त टिप्पणी बताती है कि भारत में सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का आलम क्या रहता है? हालांकि सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी सड़कों की बेहद जर्जर और खराब हालत की वजह से आई है। खराब सड़क लोगों की मौत की अहम वजह तो हैं मगर लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते भी कई लोग

की सुर्खियां बनीं। इस समस्या से निपटना हर किसी के लिए चुनौती बनी हुई है। इस तय से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में ज्यादातर सड़कें वाहनों के अनुकूल नहीं हैं। खराब सड़कों के अलावा गलत ड्राइविंग सेंस भी हादसों की प्रमुख वजह होते हैं। विश्व स्वास्य संगठन की रिपोर्ट है कि दुनिया-भर में, हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 5 करोड़ लोग घायल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हालात को काबू में करने के समाधान नहीं ढूंढ़े गए या ढूंढ़े जा रहे हैं। अभी हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई पहल किए हैं। इसमें लापरवाह चालक को अधिकतम सजा दिलाने, सड़कों की बनावट में सुधार, चालकों को प्रशिक्षण आदि हैं। लेकिन इन पहलकदमी से थोड़ा अलग तरीके से भी सोचना होगा। होता यह है किसी की गलती से अगर घर का मुखिया या कमाने वाला मर जाता है या हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है तो उसे बेहद मामूली रकम मिलती है। सरकार को इस मसले पर समझदारी और सख्ती दोनों दिखानी होगी। पीड़िता परिवार को मुआवजा ठीक-ठाक मिले, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। आखिर लापरवाही से गाड़ी चलाने के नियमों में इतने छेद क्यों हैं या उसे कमजोर क्यों बनाया गया है? ज्यादा देर करने से मामला खराब होता जाएगा।

''संतुलित और समावेशी'

पेरिस जलवायु समझौते पर होने वाला फैसला 2020 से लागू होना है, जिसका मकसद औद्योगिकीकरण से पहले के तापमान से ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार साल 2020 तक अगर दुनिया, जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम जलवायु परिवर्तन के जोखिम को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु में इंसान के मुकाबले ज्यादा तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने नियंतण्र नेताओं को इस विषय पर पहले ही चेताया है और कहा है कि यह हमारे दौर का एक अहम परिभाषित मुद्दा है। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों पर सहमति बनने की संभावना के बीच 14 दिसम्बर तक चलने वाले जलवायु सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस सम्मलेन से सकारात्मक उम्मीद जताई है। असल में भारत को उम्मीद है कि कॉप-24 विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के सामने मौजूद चुनौतियों को समझेगा। उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन से निकलने वाला परिणाम ''संतुलित और समावेशी' होना चाहिए। वास्तव में अधिकांश विकासशील देश अति संवेदनशीलता, विकास की प्राथमिकता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा की मांग और स्वास्य ढांचा उपलब्ध कराने के मामले में अभी शुरु आती स्तर पर खड़े हैं। ऐसे में भारत को इस सम्मेलन में समयबद्ध तरीके से लागू होने वाले दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की भी उम्मीद है। लेकिन इस सम्मलेन में विकसित और विकासशील देशों के बीच टकराव की नौबत आ सकती है। दरअसल, इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए पेरिस नियमावली को मंजूरी दी जानी है। नियमावली तैयार है, लेकिन विकसित देशों के रु ख के कारण विकासशील और गरीब देश इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। यूरोपीय देश हालांकि प्रतिबद्ध हैं। लेकिन तीन बड़े देशों के रुख, ग्लोबल हरित फंड में अपेक्षित राशि जमा नहीं होने से विकासशील और गरीब देशों की तरफ से वित्तीय जरूरतों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। समय कम है क्योंकि 2020 तक पेरिस समझौते का पूरी तरह से क्रियान्वयन किया जाना है। भारत और अन्य विकासशील देशों ने आरोप लगाया है कि धनी देश जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए तय सिद्धांत से पीछा छुड़ाने में लगे हैं, जिसके तहत सबकी साझी जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ विकसित देशों का दायित्व उनके सामर्य के अनुसार अपेक्षाकृत बड़ा रखने पर सहमति बनी हुई है। विकासशील देशों ने अपनी नाराजगी यहां चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान कई बार जाहिर की। यह सम्मेलन 2020 में वायुमंडल में ग्रीन-हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने की नियमावली तय करने के लिए बुलाया गया है। इस विषय पर यहां वार्ताएं अब महत्त्वपूर्ण दौर में हैं। बातचीत में अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में विकसित देशों का प्रयास है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के ''साझा प्रयास पर सामर्य के अनुसार कम-बेसी दायित्व' (सीबीडीआर) डालने के सिद्धांत को हल्का किया जाए। भारत और अन्य विकसित देश इस बात का विरोध कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पोलैंड जलवायु सम्मेलन का परिणाम सकारात्मक हो जिससे पेरिस जलवायु समझौता ठीक से लागू किया जा सके। साथ ही हमें समझना होगा की ऊर्जा संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करके ही हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं।

सत्संग

ध्यान

रहस्यवाद को, आध्यात्मिकता को सरल व तार्किक तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें, ग्रहण कर सकें। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं, जो आसान चीजों को भी रहस्यमय या दैवीय बनाने में लगे हैं। अगर कहीं घंटी बजती है या कोई फूल गिरता है या फिर अगर बिजली चली जाती है, तो लोग इसमें दैवीय आयाम ढूंढ़ने लगते हैं। दैवीय आयाम को इंसानों की पहुंच में लाने के बजाय वे लोग जीवन के सहज व सरल पक्षों को दूसरे आयामों में ले जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि आप ध्यान का इस्तेमाल अपनी समस्याओं के समाधान के तौर पर करने की कोशिश मत कीजिए। सवाल है कि क्यों? हमें अपनी समस्याओं के समाधान में ध्यान का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? दरअसल, यह तो कुछ ऐसी ही बात हो गई कि मामूली से जुकाम को ठीक करने के लिए आप कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करें। मामूली से जुकाम को संभालने के लिए रुमाल काफी है। जुकाम में आपको कुछ दिनों तक नाक बहानी होगी, अदरक या काली मिर्च की चाय पीनी होगी और यह अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप मानव अस्तित्व की सबसे बुनियादी समस्या से निबटने की कोशिश करते हैं तो बाकी सभी समस्याएं तुच्छ और अर्थहीन नजर आती हैं। अगर आप इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जुकाम ठीक करने के लिए कीमो का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। यह बेहद अफसोस की बात है कि जब आप ध्यान करते हैं, केवल तभी आपके मन में कुछ स्पष्टता रहती है, बाकी समय आपके मन में भारी हलचल रहती है। इसकी वजह है आपके भीतर बुनियादी तौर पर एक भ्रम है। हम ईशा क्रिया द्वारा इसको सरल तरीके से दूर करने की कोशिश करते हैं। क्रिया के दौरान कहा जाता है- ''न ही मैं शरीर हूं और न ही मन हूं।' अगर आपने यह चीज अनुभव के स्तर पर समझ ली तो आपकी बाकी समस्याएं झटके में गायब हो जाएंगी। अगर आप अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति को जानते तो ये सारी चीजें आपके लिए महज एक खेल होतीं।

फोटोग्राफी...

कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर में बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ''महा आरती' करते पुजारी।

कमजोर वैश्विक रुख से शेयर बाजारों में मामूली बढ़त

मुंबई। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में शेयर बाजारों में शुक्रवार को हल्की तेजी रही। रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक के चलते निवेशक बाजार से दूर रहे। वैश्विक वृद्धि को लेकर चिंता तथा अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध से जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित होने से एशिया के अन्य बाजारों में गिरावट दर्ज की गयी। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 33.29 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 35,962.93 अंक पर बंद हुआ।

एनएसई निफ्टी भी 13.90 अंक यानी 0.13 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 10,805.45 अंक पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा सत्र है जब सूचकांक में तेजी रही।आरबीआई निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार सुबह शुरू हुई। यह बैठक केंद्रीय बैंक के लिये नई आर्थिक पूंजी रूपरेखा (ईसीएफ) तथा कम-से-कम कुछ बैंकों के लिये तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) नियमों में ढील जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा के लिये हुई है। नव नियुक्त गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में निदेशक मंडल की यह पहली बैठक है। लाभ में रहने वाले प्रमुख शेयरों में भारती एयरटेल, यस बैंक, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड और आईसीआईसीआई बैंक 5.32 प्रतिशत तक मजबूत हुए।वहीं नुकसान में रहने वाले प्रमुख शेयरों में विप्रो (1.67 प्रतिशत), एचडीएफसी (1.65 प्रतिशत), एल एंड टी (0.79 प्रतिशत) तथा बजाज आटो (0.71 प्रतिशत) शामिल हैं। इस बीच, कारोबार के दौरान डालर के मुकाबले रुपया 14 पैसे टूटा।एशियाई बाजारों में कोरिया का कोस्पी 1.25 प्रतिशत, जापान का निक्केई 2.02 प्रतिशत, हांगकांग का हैंग सेंग 1.62 प्रतिशत तथा शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.53 प्रतिशत नीचे आये।यूरोपीय बाजारों में शुरूआती कारोबार में फ्रैंकफर्ट का डीएएक्स 1.46 प्रतिशत तथा पेरिस का सीएसी 1.21 प्रतिशत नीचे आये। लंदन का एफटीएसई भी 1.13 प्रतिशत टूटा।

सोने की कीमत 32,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर

नयी दिल्ली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना स्थिर रुख के साथ 32,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। हालांकि, औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की कमजोर मांग की वजह से चांदी की कीमत 200 रुपये टूटकर 38,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव क्रमशः 32,220 रुपये और 32,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रुख के साथ बंद हुआ। इसी प्रकार गिन्नी का भाव 25,000 रुपये प्रति आठ ग्राम पर स्थिर रहा।

वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोने का भाव घटकर 1,239.58 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी का मूल्य घटकर 14.68 डॉलर प्रति औंस रह गया। हाजिर चांदी का भाव 200 रुपये की हानि के साथ 38,600 रुपये और साप्ताहिक डिलीवरी में चांदी का भाव 221 रुपये की हानि के साथ 38,130 रुपये प्रति किलो रह गया। इसके अलावा चांदी सिक्का लिवाल 74,000 रुपये और बिकवाल 75,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर पूर्ववत बना रहा।

जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए परिचालन में स्वतंत्रता जरूरी : आईएमएफ

वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिये केंद्रीय बैंक की परिचालन में आजादी काफी महत्वपूर्ण है। उर्जित पटेल के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा देने के बाद देश में केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता को लेकर बहस तेज होने के बीच आईएमएफ अधिकारी का यह बयान आया है। उल्लेखनीय है कि पटेल ने इसी सप्ताह सोमवार को 'निजी कारणों' का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पटेल और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद काफी बढ़ गया था।

उर्जित पटेल के इस्तीफे के अगले ही दिन, मंगलवार को सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शक्तिकांत दास को तत्काल प्रभाव से आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। आईएमएफ के निदेशक (संवाद) गैरी राइस ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरह किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए परिचालनगत स्वतंत्रता' महत्वपूर्ण है। राइस ने आरबीआई के हालिया घटनाक्रम पर एक सवाल के जवाब में यह बात कही। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अनुरूप है। राइस ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव दिखाता है कि केंद्रीय बैंक के लिए उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कामकाज की स्वतंत्रता कितनी अहम है। उन्होंने कहा कि आरबीआई आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है और आईएमएफ के साथ मिलकर काम करने वाला उसका समकक्ष एवं अहम सहयोगी है।

कृषि ऋण माफी चुनावी वादों का हिस्सा नहीं होना चाहिए : रघुराम राजन

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने शुक्रवार को कहा कि कृषि ऋण माफी जैसे मुद्दों को चुनावी वादा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि ऐसे मुद्दों को चुनाव अभियान से अलग रखा जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इससे ना केवल कृषि क्षेत्र में निवेश रुकता है, बल्कि उन राज्यों के खजाने पर भी दबाव पड़ता है जो कृषि ऋण माफी को अमल में लाते हैं।

गौरतलब है कि पिछले पांच साल के दौरान राज्यों में होने वाले चुनावों में किसी ना किसी राजनीतिक दल ने कृषि ऋण माफी का वादा किया है। हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और कृषि ऋण माफी कई पार्टियों के घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। राजन ने कहा, ''मैं हमेशा से कहता रहा हूं और यहां तक कि मैंने चुनाव आयुक्त को भी

पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे मुद्दों को चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कृषि ऋण माफ करने से किसानों का भला होने वाला है? क्योंकि किसानों का एक छोटा समूह ही है जो इस तरह का ऋण पाता है।''।

वह यहां 'भारत के लिए एक आर्थिक रणनीति' रपट जारी करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, '' कृषि ऋण माफी का अक्सर फायदा उन लोगों को मिलता है जिनके बेहतर संपर्क होते हैं ना कि गरीबों को। दूसरा इससे प्रायः उस राज्य की राजकोषीय स्थिति के लिए कई समस्याएं पैदा होती हैं जो इसे लागू करते हैं और मेरा मानना है कि दुर्भाग्यवश इससे कृषि क्षेत्र में निवेश भी घटता है। राजन ने कहा कि आरबीआई भी बार-बार कहता रहा है कि ऋण माफी से ऋण संस्कृति भ्रष्ट होती है, वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट पर भी दबाव पड़ता है।

राजन ने कहा, ''मेरा मानना है कि किसानों को भी उनके हक से कम नहीं मिलना चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां वह एक सक्रिय कार्यबल बन सकें। इसके लिए निश्चित तौर पर अधिक संसाधनों की जरूरत है, लेकिन क्या ऋण माफी सर्वश्रेष्ठ

विकल्प है, मेरे हिसाब से इस पर अभी बहुत विचार करना बाकी है। राजन सितंबर 2016 तक तीन साल के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। इस समय वह शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

राफेल पर सुप्रीम फैसले के बाद बोले अनिल अंबानी 'हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध'

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राफेल विमान सौदे के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को रद्द करने और एसआईटी जांच के लिए मना किए जाने के बाद रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी का बयान आया है. अनिल अंबानी ने की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर दाखिल की गई सभी जनहित याचिकाओं को खरिज कर दिया है. उन्होंने कहा रिलायंस ग्रुप और मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए थे, सभी आरोप आधारहीन और राजनीति से प्रेरित थे.

सरकार की योजनाओं में पूरा योगदान रहेगा

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सरकार की योजना 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' के लिए हमारा पूरा योगदान रहेगा. साथ ही हम अपने फ्रांस के महत्वपूर्ण साझेदार दसॉल्ट एविशन का भी पूरा सम्मान करते हैं. इससे पहले शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.

सौदे की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं मिली : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायाल में सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस सौदे की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है. इसलिए इसकी एसआईटी जांच नहीं होगी. सीजेआई ने कहा कि राफेल विमान सौदे में कीमतों की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है. हम कुछ लोगों की धारणा के आधार पर फैसला नहीं दे सकते हैं. राफेल सौदे में कोई धांधली या अनियमितता नहीं है. राफेल विमान की गुणवत?ता पर कोई शक नहीं है. देश को अच्छे विमानों की जरूरत है तो राफेल डील पर सवाल क्यों?

गौरतलब है कि राफेल मामले में दो वकील एमएल शर्मा और विनीत ढांडा के अलावा एक गैर सरकारी संस्था ने जनहित याचिकाएं दाखिल कर सौदे पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले सुनवाई के दौरान सीजेआई द्वारा तलब करने पर वायुसेना के अधिकारी भी कोर्ट पहुंचे थे. एयर वाइस मार्शल चलपति कोर्ट नंबर एक में मौजूद थे और सीजेआई रंजन गोगोई के सवालों का जवाब देते हुए बताया था कि आखिर राफेल की जरूरत क्यों है?

नवंबर में महंगाई दर पर लगी लगाम, 3 महीने में सबसे कम होकर 4.64 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली। नवबंर में थोक महंगाई दर के मोर्चे पर भी राहत मिली है. नवबंर में थोक महंगाई दर अक्टूबर के 5.28 फीसदी से घटकर 4.64 फीसदी रही है. थोक महंगाई दर तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है. इसकी अहम वजह सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तूओं की कीमतें नरम रहना है. अक्टूबर में थोक मुद्रास्फीति 5.28 प्रतिशत थी जबकि पिछले साल नवंबर में यह 4.02 प्रतिशत थी. वहीं, सितंबर की थोक महंगाई दर 5.13 फीसदी से संशोधित करके 5.22 फीसदी की गई है.

सब्जियां हुईं सस्ती

शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में खाद्य वस्तूओं की कीमत में 3.31 प्रतिशत अवस्फीति दर्ज की गई है जबकि नवंबर में यह 1.49 प्रतिशत थी. सब्जियों की कीमतें घटी हैं और नवंबर में इसमें 26.98 प्रतिशत अवस्फीति देखी गई जबकि अक्टूबर में यह 18.65 प्रतिशत थी.

पेट्रोल-डीजल में कटौती से राहत

वहीं, नवंबर में 'ईंधन और बिजली' श्रेणी में मुद्रास्फीति 16.28 प्रतिशत के स्तर पर उच्च बनी रही, लेकिन यह अक्टूबर की 18.44 प्रतिशत की मुद्रास्फीति के स्तर से कम है. इसकी अहम वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटना है. खाद्य वस्तुओं में आलू में मुद्रास्फीति नवंबर में 86.45 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही. जबकि प्याज और दालों में क्रमशः 47.60 प्रतिशत और 5.42 प्रतिशत कर अवस्फीति दर्ज की गई.

तीन महीने में सबसे कम महंगाई

नवंबर की 4.64 प्रतिशत मुद्रास्फीति पिछले तीन महीनों में सबसे कम है. इससे पहले अगस्त में मुद्रास्फीति 4.62 प्रतिशत रही थी. इस हफ्ते की शुरुआत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए गए और नवंबर में वह 2.33 प्रतिशत 17 महीने के निचले स्तर पर रही.

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए मुख्य तौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर विचार करता है. अच्छे मानसून और खाद्य कीमतों के सामान्य बने रहने का हवाला देते हुए केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 2.7 से 3.2 प्रतिशत तक कर दिया था.

जल्द आएगा अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर वाला सिक्का, ये होगी खासियत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सरकार की तरफ से एक और नए सिक्के को लाने की तैयारी की जा रही है. यह सिक्का 100 रुपये का होगा और इस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर होगी. पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जन्मतिथि पर भारत सरकार की तरफ से यह स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की जा सकती है. सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था. ऐसे में सरकार उनकी 95वीं जन्मतिथि के मौके पर इसे खास बनाने की तैयारी कर रही है.

सिक्के के दूसरी तरफ अशोक स्तंभ होगा : सिक्के के एक ओर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ होगा. सिक्के के एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री का पूरा नाम देवनागरी और अंग्रेजी में लिखा जाएगा. वहीं तस्वीर के निचले हिस्से में वाजपेयी का जन्म वर्ष 1924 और देहांत का वर्ष 2018 अंकित किया जाएगा. इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा. सिक्के की बांयी परिधि पर देवनागरी लिपि में भारत और दांयी तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाएगा.

100 रुपये मूल्य वर्ग में रखा जा सकता है सिक्का : इस स्मारक सिक्के को 100 रुपये के मूल्य वर्ग में रखा जाने का प्लान है और यह सिक्का प्रचलन में नहीं आएगे. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार इस सिक्के को 3300 से 3500 रुपये की प्रीमियम दरों पर बेचे जाने की उम्मीद है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सिक्के का डिजाइन तैयार है और मुंबई टकसाल जल्द ही इसकी ढलाई का काम शुरू करने वाला है.

सिक्के में ये धातुएं होंगी शामिल : 35 ग्राम वाले इस सिक्के में 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, पांच प्रतिशत निकिल और पांच प्रतिशत जस्ता होगा. 100 रुपये की कीमत वाला यह सिक्का प्रचलन में नहीं आएगा. भारत सरकार सिक्के की बुकिंग के लिए समय तय करेगी और इसे प्रीमियम दरों पर बेचा जाएगा. इसे टकसाल से सीधे भी खरीदा जा सकेगा. आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इसी साल 16 अगस्त को 93 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था. उन्होंने तीन बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की. उत्तराखंड सरकार पहले ही देहरादून एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर करने का ऐलान कर चुकी है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति लगभग तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय नीति को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामनों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति बनायी जा रही है। प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार भारत को 1,000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ÷हम इलेक्ट्रॉनिक नीति पर काम कर रहे हैं। हमने उसे लगभग अंतिम रूप दे दिया है। हमने हरसंभव व्यापक विचार-विमर्श किया है।÷ मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को चिकित्सा, रक्षा और ऑटोमोबाइल सामान के निर्माण पर ध्यान देने को कहा। प्रसाद ने कहा, ÷हम भारत को एक हजार अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जल्द ही इसकी शुरूआत करेंगे।÷ उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में 240 कंपनियां मोबाइल फोन और उसके कलपुर्जों का निर्माण कर रही है।

प्रसाद ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा मोबाइल फोन विनिर्माण के गढ़ के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को उभरते उद्योग के तौर पर देख रहे हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक पर पहली राष्ट्रीय नीति को 2012 में लागू किया गया था। उसमें देश में विनिर्माण इकाई लगाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं देने की बात कही गयी थी।

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने किया स्पार्कल 2018 का उद्घाटन

सूरत। वायब्रंट गुजरात समिट-2019 अन्तर्गत द सदर्न गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित प्रदर्शनों की क्षेणी में गुजरात की सबसे बड़ी जेम एण्ड ज्वैलरी प्रदर्शन सूरत स्पार्कल-2018 का उद्घाटन शुक्रवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री गणपतभाई वसावा द्वारा किया गया।

सरसाणा स्थित सूरत इटरनेशनल एक्जिबिशन एण्ड कनेवेशन सेंटर में 14 से 16 दिसंबर तक सूरत स्पार्कल 2018 का आयोजन किया गया है। इस एक्जिबिशन में 10,000 से अधिक व्यापारी मुलाकात के लिए आने वाले है।

इस अवसर पर आस्ट्रेलिया के कोन्सूलेट जनरल टोनी ह्यूबर, चेंबर आफ कामर्स के प्रमुख हेतल मेहता, विधायक विवेक पटेल, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक डी.आर पटेल, सूरत डायमंड एसोसिएशन के प्रमुख बाबुभाई गुजराती, सेवती भाई शाह, स्पार्कल के चेयरमैन दिनेश भाई नावडिया सहित शहर के कई गणमान्य उपस्थित रहे।

वैश्विक डायमंड व्यवसाय में सूरत हीरे की तरह दुनिया का ध्यान खीच रहा है: गणपतभाई वसावा

स्पार्कल-2018 के उद्घाटन के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री गणपत भाई वसावा ने उद्बोधन में कहा कि वौश्विक डायमंड बिजनेश में सूरत ने एक चमकते हुए हीरे की तरह दुनिया का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की दूर दृष्टी के कारण ही सूरत ने पुरी दुनिया में अपने हीरे की चमक फैलाई है। जिसके परिणाम स्वरुप पिछले वर्षों से राज्य मे वायब्रंट गुजरात समिट का आयोजन हो रहा है। सूरत में भी पिछले 10 वर्षों से जेम एण्ड ज्वैलरी स्पार्कल एक्जिबिशन का सफलतापूर्व आयोजन हो रहा है। हीरा व्यवसाय के साथ जुड़े 35 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम से लाभांविंद हो रहे है। विश्व का 75 प्रतिशत हीरा सूरत में तराशा जाता है। गुजरात मात्र विकास का ग्रोथ इंजन ही नहीं अपितु ग्लोबल गेटवे आफ इंडिया बन चुका है।

स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत विद्यार्थियों ने सर्वे प्रतियोगिता आयोजित

सूरत। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत देशभर में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी योजना के तहत शहर के लिंबायत क्षेत्र स्थित सरस्वती एज्युकेशन सोसायटी संचालित सरस्वती माध्यमिक तथा उच्चत्तर माध्यमिक शाला में स्वच्छता सर्वे परीक्षा का आयोजन किया गया। बच्चों में स्वच्छता के बारे में जागरुकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता विषय पर आधारित प्रश्नपत्र में बच्चों से स्वच्छता से संबंधित कई ज्ञानवर्धक तथा प्रायोगिक पूछी गई। जिसका बच्चों ने बखूबी उत्तर दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा करने का सफल प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थियों का स्कूल की आचार्य सोनलबेन वासुदेव गवले ने अभिनंदन किया।

सोशल मीडिया पर बदनाम करने की शिकायत

सूरत। महिधरपुरा की एक महिला की एक अश्लील फोटों तथा कमेंट लिखकर फेसबुक पर अपलोड कर बदनाम करने वाले के विरुद्ध पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है।

महिधरपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इन्दरपुरा के गधेवान शेरी में रहने वाला अकबरभाई हुशैनभाई पटेल ने शिकायतकर्ता विवाहिता महिला के फोटों के साथ अश्लीलकमेंट लिखकर फेसबुक पर अपलोड कर वायरल कर दिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने साईबर क्राइम का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। विदित हो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर भोलीभाली युवतियों तथा महिलाओं के साथ दोस्ती करने का सिलसिला काफी बढ़ा है। जिसका शरारती तत्वों द्वारा नजायज फायदा उठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर ऐसे तत्वों से बचने की हिदायत दी जाती है। बावजूद इसके इस तरह हिदायत दी जाती है। बावजूद इसके इस तरह की घटनों बढती जा रही है। जिसमें फंसकर महिलाओं तथा युवतियां ब्लैक मेल हो रही है।

उधना को अरोरा बंधुओं ने साड़ी व्यापारी के साथ की लाखों की ठगी

कला जोन सिल्क मिल्स के मालिक के विरुद्ध शिकायत दर्ज

सूरत। उधना स्थित कलाजोन सिल्क मिल्स के मालिक के विरूद्ध एक कपड़ा व्यवसायी ने 13.24 लाख रुपये की साड़ी उधार में खरीद कर भुगतान के बदले जाने से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई गई है। सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बडेखा चकला, ढीगली फलिया निवासी लियाकत खान अयुब खान पठान ने आरोपी विश्वास सतीष अरोरा, अर्पित सतीष अरोरा मालिक कलाजोन सिल्क मिल्स, सोमा कानजी की वाड़ी, उधना के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें कहा गया है कि आरोपी अरोरा बन्धुओं ने फरीयादी तथा उसके साझेदार के पास से रु. 15,26,186 कीमत का उधार में साड़ियों का जत्था लिया था। उस समय आरोपियों ने 1 लाख रुपयों का चैक दिया था। बाकी का माल वापस करने की बात की थी। परन्तु बाद में न तो उन लोगों ने माल वापस की और नहीं माल का भुगतान किया बाकी की 13,24,942 रुपये मांगने पर अब अरोरा बंधुओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने अरीयादी की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी तथा विश्वासघात का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

अमरौली के अंजनी इंडस्ट्रीज में सिर टाइल्स मारकर हत्या

सूरत। अमरौली के अंजनी इंडस्टीयल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। व्यक्ति के सिर पर टाइल्स से हमला कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मृतक व्यक्ति की पहचान का प्रयास कर रही है।

अमरौली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पुलिस को किसी व्यक्ति ने सूचना दी की अंजनी इंडस्ट्रीज में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। हत्या की हुई लाश अंजन इंडस्ट्रीज विभाग-1 के खाता नं. 2,3 के पास संदिग्ध अवस्था में पाई गई है। युवक की उम्र 30 से 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। मृत व्यक्ति के सिर पर चोट के गंभीर निशान मिले है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि शहर में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। पुलिस कमिश्नर द्वारा समय पर अधिसूचना जारी कर सभी कारखानेदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने यहां काम करने वाले सभी कारीगरों तथा कर्मचारियों की जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कराए। परन्तु इस अधिसूचना का असर दिखाई नहीं पड़ता। सूरत शहर में लाखों लोग किसी न किसी धन्धे में लगकर अपना जीविकोपार्जन करते है। इन्ही लोगों के बीच कुछ असामाजिक तथा आपराधिक तत्व भी समय समय पर आपराधिक कार्यों को अंजाम देते है। पुलिस कमिश्नर के अधिसूचना का पालन स्थानीय पुलिस कराने में लापरवाही बरतती है जिससे लोग बेखौफ होकर घटना को अंजाम देते है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को चाहिए की संयुक्त अभियान चलाकर ऐसे मुहल्लों में रहने वाले लोगो क ीजांच करनी चाहिए जिनका आपराधिक इतिहास है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से सभी व्यवसायिक तथा अद्योगिक प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वारों पर सी.सी.टी.वी लगाने के भी निर्देश जारी किए जाते है परन्तु इसका पालन नहीं होता है। सी.सी.टी.वी कैमरे के लिए प्रशासन द्वारा सब्सिड़ी की भी व्यवस्था की गई है परन्तु सुरक्षा के नाम पर लोग एकजुट नहीं हो पा रहे है। जिससे इस तरह की घटनाएं बढती जा रही है।

राम मंदिर निर्माण के लिए सूरत में विराट धर्म सभा 16 दिसंबर को

सूरत। अयोध्या में श्रीराम भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के माहौल बनाने के उद्देश्य से सूरत लिंबायत क्षेत्र स्थित निलगिरी सर्कल के निकट विशाल मैदान में विराट धर्मा सभा का आयोजन किया गया है। 16 दिसंबर रविवार को होने वाले इस धर्म सभा में एक लाख से अधिक श्रोताओं के आने की उम्मीद है। विश्व हिन्दु परिषद द्वारा आयोजित इस धर्म सभा में सूरत सहित राज्यभर से हिन्दू संत एवं मठाधीश शामिल होंगे।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से कहा कि नीलगिरी मैदान में होने वाला विराट धर्म सभा ऐतिहासिक होगा। देश के करोड़ों हिन्दूओं के आस्था के केंद्र भगवान श्रीराम का मंदिर किसी भी कीमत पर बननी चाहिए। जिसके लिए हिन्दुओं को जागृत होना पड़ेगा। सम्पूर्ण भारत में इस तरह के धर्म सभा का आयोजन कर लोगों में सोई हिन्दूत्व की भावना को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। राममंदिर का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में काफी लम्बे समय से लंबित है। जिसपर जनवरी महीने से सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के रवैये से यह लगता है कि राममंदिर का मामला उनकी प्राथमिकता में नहीं है। ऐसे में उध्यादेश लाकर ही मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाया जा सकता है। जिसके लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मे ंसाधु संतों के सम्मेलन में राम मंदिर निर्माण को लेकर अहम फैसला किया जा सकता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में 31 जनवरी तथा 1 फरवरी को धर्म देश के कोने कोने स े आए साधु संतों का विशाल धर्म संसद लगेगा। जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए सम्पूर्ण भारत में माहौल तैयार करने के लिए विश्व हिन्दू परिषद द्वारा जगह-जगह धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 16 दिसंबर रविवार को लिंबायत के नीलगिरी मैदान में विराट धर्म सभा का आयोजन होगा। सांय 5 बजे से होने वाली धर्म सभा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर भगवाध्वज लगाए गए है। कार्यक्रम की तैयारियों के चलते सम्पूर्ण लिंबायत क्षेत्र भगवारंग में रंग गया है।

अमरौली में प्रेमिका के घर में घुसकर किया बलात्कार

सूरत। अमरौली में अपनी प्रेमिका के घर आए प्रेमी द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने का मामला प्रकाश में आया है। अमरौली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सलाबतपुरा के अनवर नगर झोपड़ पट्टी में रहने वाले शाहरुख खान अयुबखान पठान ने अमरौली विस्तार की लड़की के साथ सगाई हुई थी। आरोपी 1 महीने पहले अपनी प्रेमिका के घर आया था और उसने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। गौरतलब है कि जब से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के नए कानून बना है तब से कुछ लोग इसका नजायज फायदा उठा रहे है। अपनी मर्जी से मर्दों के साथ समय बीताने तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद जब दिल भर जाता है तो उस व्यक्ति से पीछा छुडाने या उनसे धन उगाही के लिए इस तरह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)